

## Release Them Now!

**We strongly condemn the motivated hounding of human rights defenders across several states and demand for their immediate release**

New Delhi, August 29, 2018

The Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS, Rajasthan) condemns the *mala fide* allegations and the coercive use of state power, in the arrest/raids of **Sudha Bharadwaj** (a civil rights and labour lawyer from Chhattisgarh; presently teaching at the National Law University, Delhi); **Gautam Navlakha** (former President of Peoples' Union for Democratic Rights and a journalist); **Anand Teltumbde** (human rights activist and management professional, writer, civil rights activist and political analyst); **Father Stan Swamy** (80-years-old human rights activist based in Ranchi); **Varavara Rao** (77-years-old poet and prominent activist) and senior activists **Arun Ferreira** and **Susan Abraham**.

The Pune police in a series of raids and arrests on the 27th and 28th of August 2018, deliberately pinned serious allegations on these activists for the Bhima Koregaon incident, ignoring the main role of the Hindutva leader Sambhaji Rao Bhide and his associates in initiating violence. A few months earlier, **Surendra Gadling** (a Maharashtra civil rights and trade union lawyer), **Rona Wilson** (an academic and activist involved in the Committee for the Defence of Political Prisoners), **Prof. Shoma Sen** (Nagpur University), **Sudhir Dhawale** (activist and publisher) and **Mahesh Raut** (activist and former Prime Minister Rural Development Fellow) were also arrested in connection with the Bhima Koregaon incident. So far all the arrests have been made citing baseless allegations and reflect a prejudiced targeting of people who have had the courage and the intellectual rigour to question the miscarriage of law and the violation of constitutional rights. They are well-known academics and human rights defenders, who have defied all odds and the possible pall of violence imposed by unlawful majoritarian fundamentalist forces. Given the absence of any credible evidence, these arrests are clearly a part of the political conspiracy to silence any dissent and critique of the party in power.

We also strongly condemn the attempt to mislead people through the deliberate use of the term 'Urban Naxals' both by BJP politicians and those in the media, who are acting in tandem with the government to create a media trial. This is an attempt to construct a hostile citizenry prejudiced against those working for the poor and marginalised with a carefully-choreographed media trial.

We are in fact proud of the academic and intellectual history of India from the time of the independence movement, and laud those who have expressed their views without hesitation. They have been a crucial support for those impacted by violence and discrimination, even at a cost to themselves. They have used non-violent means and avenues available through law and the Constitution to defend the rights of the poor and marginalised. This harassment is a blatant attempt to prevent the intelligentsia from raising their voices against injustice, oppression and exploitation. It is a prelude to making sure that the space for dissent and democratic expression is closed, and even the threats to the Constitution go unchallenged. The people of India must realise who is really trying to undermine the Indian Constitution and its values.

It is the duty of all citizens to voice their support for those who work to amplify the voices of the voiceless. We demand that the BJP governments both in Maharashtra and at the Centre stop targeting human rights workers for narrow political gains. The (mis)use of such repressive legal instruments, makes a mockery of the rule of law, and will have very grave consequences for the Indian polity.

In solidarity,  
Aruna Roy, Nikhil Dey, Shankar Singh for MKSS Rajasthan.

For more information, please contact:  
Amit - 9873522104

प्रेस विज्ञप्ति  
मज़दूर किसान शक्ति संगठन

## सामाजिक कार्यकर्ताओं को फ़ौरन रिहा करो!

हम अनेक राज्यों में मानव-अधिकार रक्षकों के सुनियोजित दमन और प्रताड़ना की कड़ी निंदा करते हैं और उनकी तुरंत रिहाई की माँग करते हैं!

नई दिल्ली, अगस्त 29, 2018

मज़दूर किसान शक्ति संगठन (राजस्थान) **सुधा भारद्वाज** (छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ वक़ील और वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय विधि संस्थान में शिक्षिका), **गौतम नवलखा** (PUDR के पूर्व अध्यक्ष और पत्रकार), **आनंद तेलतंबड़े** (मानवाधिकार एवं दलित कार्यकर्ता, प्रबंधन विशेषज्ञ, लेखक एवं राजनैतिक विश्लेषक), **फ़ादर स्टेन स्वामी** (राँची के 80 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता), **बराबर राव** (77 वर्षीय कवि एवं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता), और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता **अरुण फ़रेरा** एवं **सुज़ैन अब्राहम** पर लगाए बेबुनियाद आरोपों और उनकी गिरफ़्तारी/दबिश की कठोर निंदा करता है।

ज्ञातव्य है कि 27 और 28 अगस्त को पुणे पुलिस ने जगह-जगह छापेमारी के बाद इन कार्यकर्ताओं पर गम्भीर आरोप लगाकर उन्हें भीमा कोरेगाँव में हुई हिंसा के लिए दोषी ठहराया है जबकि इस मामले में हिंदुत्व-वादी नेता सम्भाजी राव भिड़े और उनके साथियों की हिंसा भड़काने में भूमिका को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। कुछ ही महीनों पहले, **सुरेन्द्र गाडलिंग** (महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियन और मानवाधिकार मामलों के वक़ील), **रोना विल्सन** (शिक्षिका और राजनैतिक बंदियों को बचाने के लिए बनी समिति की सदस्या), **प्रोफ़ेसर शोमा सेन** (नागपुर विश्वविद्यालय), **सुधीर धवाले** (प्रकाशक एवं सामाजिक कार्यकर्ता) और **महेश राउत** (सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व 'प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फ़ेलो') को भी इसी तरह भीमा कोरेगाँव मामले में दोषी बताते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया था। अभी तक ये सारी गिरफ़्तारियाँ बेबुनियाद आरोपों के आधार पर की गयी हैं जो दिखाता है कि जो लोग संवैधानिक हकों के छीने जाने या क़ानून के ग़लत इस्तेमाल के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का साहस या बौद्धिक क्षमता रखते हैं उन्हें जान-बूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये सभी लोग जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिक्षक और चिंतक हैं जो बहुसंख्यक-वादी कट्टरपंथियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा के खिलाफ़ पूरी ताक़त से खड़े हुए हैं। जब पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ़ कोई विश्वसनीय सबूत ही नहीं है तो इनकी गिरफ़्तारी और प्रताड़ना सीधे इस बात का संकेत देती है कि जिन भी लोगों ने सत्ताधारी दल के खिलाफ़ सवाल खड़े किए या उनकी आलोचना की उन्हें राजनैतिक षड्यंत्र के तहत फँसाया गया है।

हम भाजपा के नेताओं और मीडिया के कुछ लोगों द्वारा 'शहरी नक्सल' जैसे शब्दों के गलत इस्तेमाल से लोगों को गुमराह करने और सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलकर एक 'मीडिया ट्रायल' जैसी स्थिति बनाने की भी कड़ी निंदा करते हैं। इस सुनियोजित 'मीडिया ट्रायल' के जरिए गरीबों और वंचितों के लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह और दुर्भावना फैलाने की कोशिश की जा रही है।

हमें तो भारत की आज़ादी के संघर्ष के समय से ही चली रही जन-पक्षधर शैक्षिक और बौद्धिक धरोहर पर फ़क्र है और हम उन सभी लोगों को प्रशंसा का पात्र मानते हैं जो बिना डरे हाशिए पर धकेले गए लोगों के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते आए हैं। इन लोगों की वजह से हिंसा और भेदभाव झेल रहे लोगों को बहुत मदद मिली है। इन लोगों ने अहिंसक तरीकों और क़ानून और संविधान के दायरे में काम करते हुए गरीब और हाशिए पर धकेले लोगों के लिए काम किया है चाहे इसकी जो भी कीमत इन्हें स्वयं चुकानी पड़ी हो। इन लोगों को इस तरह प्रताड़ित करना अन्याय, शोषण और दमन के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोगों को रोकने की एक नापाक कोशिश है। यह एक शुरुआत है ऐसा माहौल बनाने की जिसमें प्रतिरोध और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सभी जगहों को ख़त्म कर दिया जाए और संविधान पर मँडरा रहे ख़तरों को भी चुनौती ना दी जाए। भारत के अवाम को यह समझना होगा कि कौन-सी ताक़तें वाक़ई भारत के संविधान और उसके मूल्यों को नेस्तनाबूद करने पर आमादा हैं।

मुल्क के सभी नागरिकों का फ़र्ज़ है कि बे-आवाज़ लोगों की आवाज़ को उठाने वाले ऐसे लोगों की मदद के लिए वे आगे आएँ। हम माँग करते हैं कि महाराष्ट्र और केंद्र की भाजपा सरकारें अपने संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थों के लिए इस तरह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना बंद करें और दमनकारी क़ानूनी हथियारों के इस्तेमाल से इस तरह क़ानून की खिल्ली उड़ाना बंद करें क्योंकि भारतीय राजनीति को इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

ज़िंदाबाद!

**अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह एवं मज़दूर किसान शक्ति संगठन के सभी साथी**

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

अमित 98735 22104